

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति एस. एस. संधावालिया और न्यायमूर्ति पी.सी. जैन और एस.सी. मित्तल के समक्ष

जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेड - याचिकाकर्ता,

बनाम

आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्कल III, मयूर भवन, नई दिल्ली और एक अन्य - उत्तरदाता।

1977 की सिविल रिट याचिका संख्या 1501

6 दिसंबर, 1978

आयकर अधिनियम (1961 का XLIII) धारा 2 (14)। (22ए), 55ए और 133(6))-धारा 55ए- चाहे वह विशेष रूप से 'पूंजीगत लाभ' से संबंधित अध्याय IV के भाग 'ई' के लिए हो - आयकर अधिकारी द्वारा स्वीकार की गई संपत्ति का मूल्यांकन और मूल्यांकन पूरा हो गया हो - करदाता-आयकर अधिकारी के परिसरों में की गई तलाशी के अनुसरण में शुरू की गई कार्यवाही - क्या ऐसी संपत्ति के मूल्य का पता लगाने के लिए मूल्यांकन अधिकारी की सहायता ले सकते हैं।

यह अभनिर्धारित किया गया कि यह सही है कि आयकर अधिनियम 1961 का अध्याय IV "कुल आय की गणना" से संबंधित है, लेकिन जिस तरह से विधायिका ने अपने विवेक से इस अध्याय को अलग-अलग शीर्षों ए से एफ के तहत विभाजित किया है, उसे आसानी से अनदेखा नहीं किया जा सकता है। चूंकि अधिनियम की धारा 55 ए भाग "ई-पूंजीगत लाभ" में होती है, इसलिए यह केवल पूंजीगत लाभ पर लागू होती है।

(पैरा 7)

यह अभनिर्धारित किया गया कि चूंकि आयकर अधिकारी सीधे करदाता को किसी संपत्ति के मूल्यांकन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता कर सकता है, इसलिए वह मूल्यांकन अधिकारी की सहायता से इसे पूरा करने के लिए अपनी शक्तियों का भी उपयोग कर सकता है। छिपी हुई आय का पता लगाना अधिनियम की धारा 133 (6) के अर्थ के भीतर एक 'कार्यवाही' है और आयकर अधिकारी धारा 131 से 135 द्वारा निहित सभी शक्तियों का उपयोग कर सकता है। तलाशी के अनुसरण में, यदि ऐसा प्रतीत होता है कि किसी संपत्ति पर बड़ी मात्रा में बेहिसाब धन खर्च किया गया है, तो आयकर अधिकारी ऐसी संपत्ति की लागत के बारे में पूछताछ कर सकता है। वह इसी तरह इस उद्देश्य के लिए मूल्यांकन अधिकारी की सहायता ले सकता है।

(पैरा 9)

माननीय न्यायमूर्ति एम आर शर्मा और माननीय न्यायमूर्ति एस एस सिद्धू सहित इस न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति डी बी द्वारा 28 जुलाई, 1977 को मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय के लिए एक बड़ी पीठ को मामला भेजा गया। पूर्ण पीठ ने अंततः 8 दिसंबर, 1978 को गुण-दोष के आधार पर मामले का फैसला किया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि याचिकाकर्ता को निम्नलिखित राहत दी जाए:-

- प्रतिवादी संख्या 2 को अनुलग्नक 'पी-2' में दिए गए निर्देश का पालन करने से रोकें।
- प्रतिवादी संख्या 2 को 6 दिसंबर, 1976 के पत्र को अनुलग्नक 'पी -3' को वापस लेने की आवश्यकता है।
- प्रतिवादी संख्या 2 को मई, 1971 और/या मई, 1971 में पूरा किए गए निर्माण की लागत के संबंध में वाउचर और विभिन्न अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर जोर देने से रोकें।
- कोई अन्य राहत जो जिसे याचिकाकर्ता को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार पाया जा सकता है।

यह भी अनुरोध किया जाता है कि याचिका का निर्णय लंबित रहने तक प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाई जाए और प्रतिवादियों को नोटिस के साथ अंतरिम राहत दी जाए। यह भी

प्रार्थना की जाती है कि अनुलग्नक की प्रमाणित प्रतियां और प्रतिवादियों को पांच दिन का नोटिस प्रस्तुत किया जाए।

भागीरथ दास, बीके गुप्ता और जसवंत जैन, याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील ।
डी. एन. अवस्थी, और बी. के. झिंगन, उत्तरदाताओं के लिए वकील।

न्यायमूर्ति एस.सी. मित्रल

- 1) इस पीठ के समक्ष निर्धारण का प्रश्न यह है कि क्या इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में आयकर अधिकारी द्वारा संबंधित समय पर मिल के मूल्य का पता लगाने के लिए मूल्यांकन अधिकारी को भेजा गया संदर्भ वैध है?
- 2) मुख्य तथ्य यह है कि 1970 और मई 1971 में मेसर्स जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेड ने, जिसे बाद में कंपनी के रूप में संदर्भित किया गया था, हिसार में अपने परिसर में स्ट्रिप-स्कॉलप मिल शेड का निर्माण किया, जिसे बाद में मिल के रूप में संदर्भित किया गया। 31 दिसंबर, 1971 को समाप्त वर्ष (आकलन वर्ष 1972-73) के लिए, कंपनी ने अपनी रिटर्न में मिल का मूल्य 15,30,064.84 रुपये प्रति यूनिट लगाया। मूल्यांकन को आयकर अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, जिन्होंने उस समय इस मामले को देखा था, दिनांक 7 जनवरी, 1974 के अपने आदेश द्वारा। बाद के मूल्यांकन वर्षों 1973-74, 1974-75 के लिए, मिल के उपर्युक्त मूल्य को दोहराया गया, जिसमें उचित मूल्यहास दिखाया गया। संबंधित आयकर अधिकारियों ने दिनांक 16 फरवरी, 1976 और 2 मार्च, 1976 के अपने आदेशों में मूल्यांकन को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार, उपर्युक्त तीन वर्षों के लिए मूल्यांकन कार्यवाही सभी मामलों में पूरी हो गई है।
- 3) आकलन वर्ष 1975-76 के लिए, कंपनी द्वारा 29 अगस्त, 1976 को दाखिल रिटर्न लंबित था, जब 26 नवंबर, 1976 को आयकर अधिकारी (प्रतिवादी संख्या 1) ने आयकर अधिनियम की धारा 56-ए के तहत कार्य करने का इरादा रखते हुए, जिसे बाद में अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया, मूल्यांकन अधिकारी (प्रतिवादी संख्या 2) को मूल्यांकन वर्ष 1972-73 के लिए मिल का मूल्यांकन करने के लिए लिखा। दिनांक 6 दिसम्बर, 1976 के अपने पत्र (अनुलग्नक पृष्ठ 3) द्वारा मूल्यांकन अधिकारी ने कंपनी से अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी की स्थापना की तारीख से 31 दिसम्बर, 1972 तक संपत्ति, तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा के चित्रों का पूरा सेट उपलब्ध कराने को कहा। मिल का मूल्यांकन करने की दृष्टि से 1 मार्च, 1977 को मूल्यांकन अधिकारी ने कंपनी के परिसर का दौरा किया। कंपनी ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। इसके बाद, कंपनी को मूल्यांकन अधिकारी से दिनांक 9 और 15 मार्च, 1978 के पत्र (अनुलग्नक पृष्ठ 5 और पृष्ठ 6) प्राप्त हुए जिसमें कंपनी को संबंधित अवधि के लिए मिल के निर्माण में किए गए खर्च के वाउचर और उसके पुनर्मूल्यांकन के लिए कुछ अन्य जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। उस स्तर पर, अपने उत्तर (अनुबंध पृष्ठ 7) द्वारा, कंपनी ने मूल्यांकन अधिकारी के उक्त जानकारी मांगने के अधिकार पर इस आधार पर आपत्ति जताई कि वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 के लिए मूल्यांकन कार्यवाही पूरी होने के कारण, कंपनी के लिए मूल्यांकन अधिकारी की मांग का अनुपालन करने का कोई अवसर नहीं था। चूंकि उन्होंने ऊपर उल्लिखित दो पत्रों में निहित निर्देशों के अनुपालन पर जोर दिया, इसलिए कंपनी ने अधिनियम की धारा 55-ए के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग में मूल्यांकन अधिकारी की सहायता लेने के लिए आयकर अधिकारी के अधिकार को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की। आगे की कार्यवाही से पहले, यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान आकलन वर्ष 1975-76 की कार्यवाही समाप्त हो गई। कंपनी के वकील ने मूल्यांकन आदेश का संदर्भ दिया, लेकिन रिट याचिका के निर्णय के लिए, इसकी एक प्रति रिकॉर्ड पर रखना आवश्यक नहीं समझा।

- 4) विभाग का मामला यह है कि जून 1974 में याचिकाकर्ता कंपनी समेत जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज की तमाम चिंताओं को लेकर कारोबारी और आवासीय परिसरों की तलाशी ली गई थी। एकत्र की गई सामग्री को इंटेलिजेंस विंग द्वारा विधिवत संसाधित किया गया था। अन्य बातों के साथ-साथ इसकी अंतिम रिपोर्ट यह थी कि मिल के निर्माण पर बड़ी मात्रा में बेहिसाबी धनराशि खर्च की गई प्रतीत होती है। तदनुसार, आयकर अधिकारी को मिल के निर्माण की लागत के संबंध में जांच करने की सलाह दी गई थी। यह अधिनियम पर्याप्त प्रावधान करता है और आयकर अधिकारियों को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है, जो किसी करदाता की कुल आय की गणना में लगे हुए हैं, ताकि छिपी हुई आय का पता लगाया जा सके। इस प्रयोजन के लिए, कंपनी को मिल के मूल्य के अनुसार एक अनुमोदित मूल्यांकक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। चूंकि उक्त मूल्यांकनकर्ता द्वारा दिया गया मूल्यांकन खुफिया अधिकारियों द्वारा खोजे गए मूल्यांकन से काफी कम पाया गया था, इसलिए मिल के निर्माण की सटीक लागत का पता लगाने के लिए आगे की जांच आवश्यक समझी गई। आयकर विभाग के मूल्यांकन प्रकोष्ठ का संदर्भ देना। इस तरह मूल्यांकन अधिकारी की सहायता मांगी गई है।
- 5) अपने पत्र (अनुबंध पी. 2) में, आयकर अधिकारी ने मूल्यांकन अधिकारी को प्रासंगिक समय पर मिल के मूल्य का पता लगाने के लिए कहा है, अधिनियम की धारा 55-ए का उल्लेख किया है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, मूल्यांकन अधिकारी ने अनुबंध पी 2 के आधार पर कार्रवाई की। कंपनी के वकील का तर्क है कि जहां भी मूल्यांकन अधिकारी की सहायता आवश्यक मानी जाती है, अधिनियम में प्रावधान है। इस संबंध में अधिनियम की धारा 269-एल का संदर्भ दिया गया था, जो वर्तमान मामले में लागू नहीं होती है। अधिनियम की धारा 55-ए के संबंध में, विद्वान वकील का तर्क है कि यह इस मामले पर लागू नहीं होता है। अधिनियम की धारा 55-ए के प्रासंगिक भाग में लिखा है: -

इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए किसी पूंजीगत परिसंपत्ति के उचित बाजार मूल्य का पता लगाने की दृष्टि से, आयकर अधिकारी पूंजीगत संपत्ति के मूल्यांकन को मूल्यांकन अधिकारी को भेज सकता है-

- ऐसे मामले में जहां करदाता द्वारा दावा की गई संपत्ति का मूल्य एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए अनुमान के अनुसार है, यदि आयकर अधिकारी की राय है कि इस तरह दावा किया गया मूल्य उसके उचित बाजार मूल्य से कम है;
- किसी अन्य मामले में, यदि आयकर अधिकारी की राय है-
 - कि परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य संपत्ति के मूल्य से अधिक है जैसा कि निर्धारित द्वारा दावा किया गया है, संपत्ति के मूल्य के ऐसे प्रतिशत से अधिक या इस संबंध में निर्धारित राशि से अधिक; नहीं तो
 - कि संपत्ति की प्रकृति और अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा करना आवश्यक है,

धारा 55-क में प्रयुक्त "इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए" शब्दों पर बल दिया गया है। यह खंड अधिनियम के अध्याय IV में आता है जो निम्नलिखित भागों में है:-

A- वेतन - धारा 15 से 17।

B - प्रतिभूतियों पर ब्याज- धारा 18 से 21

C - गृह संपत्ति से आय - धारा 22 से 27,

D - व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ - धारा 28 से 44 डी।

E - पूंजीगत लाभ - धारा 45 से 55 ए,

F - अन्य स्रोतों से आय - धारा 56 से 59

- 6) कंपनी के विद्वान वकील का तर्क यह है कि धारा 55-ए विशेष रूप से अध्याय IV के भाग "ई" के लिए है जो "पूंजीगत लाभ" से संबंधित है। कंपनी के विद्वान वकील के तर्क को प्रभावित करने वाले अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर बाद में चर्चा की गई है। अधिनियम की धारा 2(14) में कहा गया है:-

"पूंजीगत संपत्ति" का अर्थ है किसी करदाता द्वारा आयोजित किसी भी प्रकार की संपत्ति, चाहे वह उसके व्यवसाय या पेशे से जुड़ी हो या न हो।"

परिभाषा में कुछ चीजें शामिल नहीं हैं जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, क्योंकि हमारे सामने यह आग्रह नहीं किया गया है कि विचाराधीन मिल "पूंजीगत संपत्ति" की परिभाषा के भीतर नहीं आती है। अब यह उचित है कि "उचित बाजार मूल्य" की परिभाषा को पुनः प्रस्तुत किया जाए- धारा 2(22क) के तहत जिसका अर्थ है कि पूंजीगत परिसंपत्ति के संबंध में:

- i. वह मूल्य जो पूंजीगत परिसंपत्ति आमतौर पर प्रासंगिक तिथि पर खुले बाजार में बिक्री पर प्राप्त करेगी; और
- ii. जहां उपधारा (i) में निर्दिष्ट मूल्य का पता नहीं लगाया जा सकता है, ऐसी कीमत जो इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित की जाए;

"पूंजीगत लाभ" से संबंधित अधिनियम के अध्याय IV का भाग "ई" धारा 45 से शुरू होता है जो यह प्रावधान करता है कि पिछले वर्ष में प्रभावित पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या लाभ को धारा 53, 54, 54 बी, 54 डी और 54 ई में अन्यथा उपबंधित किया जाएगा, जिसे "पूंजीगत लाभ" शीर्षक के तहत आयकर के लिए प्रभारित किया जाएगा और इसे पिछले वर्ष की आय माना जाएगा जिसमें हस्तांतरण हुआ था। स्थान। धारा 46 परिसमापन में कंपनियों द्वारा पूंजीगत लाभ या परिसंपत्तियों के वितरण से संबंधित है। कर्तन। 47 में ऐसे लेन-देन की गणना की गई है जो धारा 45 के दायरे में नहीं आते हैं। "पूंजीगत लाभ" शीर्षक के तहत प्रभारयोग्य आय की गणना का तरीका धारा 48 में दिया गया है। पूंजीगत संपत्ति का अधिग्रहण (धारा 49); मूल्यहास योग्य परिसंपत्तियों के मामले में अधिग्रहण की लागत की गणना (धारा 50); अग्रिम धन प्राप्त (धारा 51); विवरण के तहत मामलों में स्थानांतरण के लिए विचार (धारा 52); पूंजीगत लाभ कर से मुक्त (धारा 53); निवास के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्ति की बिक्री पर लाभ (धारा 54) आदि अधिनियम के अध्याय IV के भाग "ई" में निहित अन्य मामले हैं। इस संदर्भ में, कंपनी के विद्वान वकील का तर्क यह है कि धारा 55-ए का दायरा, जैसा कि इसकी शर्तों से स्पष्ट है, पूंजीगत संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का पता लगाने तक सीमित है जो हस्तांतरण का विषय रहा है।

- 7) विभाग के वकील ने तर्क दिया है कि अध्याय 4 "कुल आय की गणना" से संबंधित है। ऐसा ही है, लेकिन जिस तरह से विधायिका ने अपने विवेक से इस अध्याय को अलग-अलग शीर्षों ए से एफ के तहत विभाजित किया है, उसे आसानी से अनदेखा नहीं किया जा सकता है। चूंकि धारा 55 ए भाग "ई-पूंजीगत लाभ" में होती है, इसलिए यह केवल पूंजीगत लाभ पर लागू होता है। किसी भी मामले में, हमारा ध्यान धारा 55-ए की ऐसी किसी भी शर्त या अध्याय IV के अन्य भागों के किसी भी प्रावधान की ओर नहीं दिलाया गया है, ताकि यह दिखाया जा सके कि धारा 55-ए, जिसमें "इस अध्याय के तहत" शब्द होते हैं, "पूंजीगत लाभ" के अलावा किसी भी लेनदेन के लिए प्रासंगिक है। पूर्वगामी कारणों से, कंपनी के विद्वान वकील के तर्क को खारिज करना मुश्किल लगता है कि अधिनियम की धारा 55-ए इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होती है।

- 8) आयकर अधिकारी की शक्तियों के संबंध में, विभाग के विद्वान वकील अधिनियम की धारा 133 (6) पर मजबूत भरोसा करते हैं:-

"आयकर अधिकारी, अपीलीय सहायक आयुक्त या निरीक्षण सहायक आयुक्त, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए-

(6) बैंकिंग कंपनी सहित किसी भी व्यक्ति को ऐसे बिंदुओं या मामलों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, या आयकर अधिकारी, अपीलीय सहायक आयुक्त या निरीक्षण सहायक आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट तरीके से सत्यापित खातों और मामलों के विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जो आयकर अधिकारी की राय में ऐसे बिंदुओं या मामलों के संबंध में जानकारी देते हैं, अपीलीय सहायक आयुक्त या निरीक्षण सहायक आयुक्त, अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के लिए उपयोगी या प्रासंगिक होगा।"

- 9) हमारे समक्ष इस बात पर विवाद नहीं किया गया है कि यदि आयकर अधिकारी सीधे याचिकाकर्ता-कंपनी से मूल्यांकन अधिकारी द्वारा मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, तो आयकर अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। तदनुसार, विभाग के विद्वान वकील ने निष्कर्ष निकाला कि एक आयकर अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो कुछ भी सीधे कर सकता है, वह मूल्यांकन अधिकारी की सहायता से किया जा सकता है। इसके बाद अधिनियम की धारा 133 (6) में होने वाले "अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही" शब्दों पर जोर दिया जाता है। यह देखा जाएगा कि छिपी हुई आय का पता लगाना एक ऐसी कार्यवाही है। अधिनियम की धारा 131 से 135 आयकर प्राधिकारियों की शक्तियों को निर्धारित करती है। धारा 131 आयकर अधिकारी और अन्य अधिकारियों को साक्ष्य आदि की खोज या उत्पादन के बारे में शक्तियां प्रदान करती है। धारा 132 द्वारा तलाशी और जब्ती की शक्ति प्रदान की गई है। इसके बाद धारा 132-ए आती है जो बही-खातों आदि की मांग करने की शक्ति प्रदान करती है। सूचना मांगने की शक्ति धारा 138 द्वारा और सर्वेक्षण की शक्ति धारा 133-ए द्वारा प्रदान की जाती है। यहां यह बताना उचित है कि "कार्यवाही" को धारा 133 ए के स्पष्टीकरण (बी) द्वारा निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: -

"कार्यवाही का अर्थ है किसी भी वर्ष के संबंध में अधिनियम के तहत कोई भी कार्यवाही जो उस तारीख को लंबित हो सकती है जिस दिन धारा के तहत शक्तियों का उपयोग किया जाता है या जो उस तारीख को या उससे पहले पूरा हो सकता है और इसमें इस अधिनियम के तहत सभी कार्यवाही भी शामिल है जो किसी भी वर्ष के संबंध में ऐसी तारीख के बाद शुरू की जा सकती है।"

धारा 134 आयकर अधिकारी और उसमें विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों को कंपनियों के रजिस्ट्रों का निरीक्षण करने की शक्ति प्रदान करती है। ऐसा होने के कारण, हमारे सामने यह तर्क नहीं दिया गया है कि याचिकाकर्ता-कंपनी सहित जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज की तलाशी "अधिनियम के तहत एक कार्यवाही" नहीं थी। जैसा कि ऊपर कहा गया है, तलाशी के परिणामस्वरूप, विभाग के आसूचना विंग ने मामले की कार्रवाई की और आयकर अधिकारी को सूचित किया, अन्य बातों के साथ-साथ ऐसा प्रतीत होता है कि मिल के निर्माण पर बड़ी मात्रा में बेहिसाबी धन खर्च किया गया है। तदनुसार, आयकर अधिकारी को मिल के निर्माण की लागत के संबंध में जांच करने की सलाह दी गई थी। इस संदर्भ में मूल्यांकन अधिकारी की सहायता ली गई है। इसका महत्व इस तथ्य में निहित है कि मिल के सही मूल्य का पता लगाने के लिए, आयकर अधिकारी ने मूल्यांकन अधिकारी (प्रतिवादी संख्या 2) के तकनीकी ज्ञान का लाभ उठाने का विकल्प चुना है, जो आयकर विभाग के अधीक्षण अभियंता (मूल्यांकन) के अलावा कोई और नहीं है। इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं है कि आयकर अधिकारी को इस मामले की पूरी जानकारी है। चीजों की प्रकृति में, मूल्यांकन अधिकारी की रिपोर्ट आयकर अधिकारी को बाध्य नहीं करेगी और कंपनी इस

मामले में अपनी बात रख सकती है। आयकर अधिकारी द्वारा मूल्यांकन अधिकारी को पत्र अनुलग्नक पी-2 में आयकर अधिनियम की धारा 55-ए का उल्लेख करने का कोई मतलब नहीं है, इसमें, जब कार्यवाही अन्यथा कानून के अनुसार है, तो गलत धारा का उल्लेख करने से उनका उल्लंघन नहीं होगा।

- 10) विभाग के विद्वान वकील द्वारा संदर्भित मामले का दूसरा पहलू यह है कि मूल्यांकन अधिकारी द्वारा कंपनी से मांगी गई जानकारी बाद के हित में है। वकील ने आगे जोर देकर कहा कि आयकर अधिकारी ने अधिनियम की धारा 147 के तहत सीधे कार्यवाही शुरू नहीं करने में कंपनी के प्रति काफी निष्पक्ष रहा है। इसके बजाय, उन्होंने मिल के मूल्य का पता लगाने में कंपनी को संबद्ध करने के लिए एक बहुत ही निष्पक्ष रास्ता चुना है और यह हो सकता है कि यदि कंपनी आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करती है, तो 1972-73 से शुरू होने वाले मूल्यांकन को फिर से खोलने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं हो सकती है।
- 11) उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, निर्णय की शुरुआत में तैयार किए गए प्रश्न का उत्तर हां में दिया गया है। रिट याचिका विफल हो जाती है और इसे खारिज किया जाता है। हालांकि, पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति एस.एस. संधावालिया, सहमत हैं।

माननीय मुख्य प्रेम चंद जैन, -मैं भी सहमत हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

हिमांशु जांगड़ा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

